

EDITORIAL

Foreword to Massive Strike

The All unions and Associations of BSNL have given a strike call for two days on Dec. 12th and 13th after dispassionately assessing the situation. The message and importance of the strike should be taken forward to every employee and executive to make it a very massive one. Preparatory Meetings as scheduled by all unions should be organized in centers with the participation of General Secretaries and CHQ office bearers. The district unions should organize centralized meetings with circle secretaries and circle office bearers. Branch level coordination should also be ensured for reaching out every employee for participation. The other tasks like Human Chain and Memo to MPs should be done effectively.

There may be information regarding positive attitude of BSNL, pushing its suggestion /approval/ appeal to DOT for permitting the company to settle wage revision as the company is in its revival mode. There may be question why then strike for two days. The reasons should be elaborated to our rank and file so that to make them to understand the compelling situation to show our anger.

The strike is not only for the question of wage revision, also for demanding the GOI to stop its steps to dismantle our tower assets by creating separate tower company and helping private telcos to make inroads in the name of strategic partner. This decision of cabinet is unfair and undemocratic as the stake holders like employees are kept in dark without any consultation or even information.

The other main issue is wage revision. Though GOI has setup 3rd PRC and accepted the recommendations and issued DPE guidelines, BSNL is not a company eligible to implement the said 3rd PRC Wages to its executives. The conditions are very stringent and no loss making units would get any wage revision as per the existing guidelines. The steps taken by the BSNL Management regarding the wage revision may be considered as sympathetic one towards its staff executives but cannot be taken as an authorized action on the basis of the existing DPE guidelines. It is reported that MOC is also having the view that it is difficult for him to go beyond cabinet decision.

When NFTE BSNL is demanding Bilateral wage negotiating committee comprising both Union side and Official side and start wage negotiation with the non executive unions , BSNL management is replying us that there is no guideline from DPE to enable them to start any negotiation with the non executives. Non Executives can get their wage revision only when they get some agreement with the management. DPE has replied back to NFTE when demanding, that the guidelines to start negotiation with workmen is in active consideration. But even if that guideline is issued, it would be helpful only when exemption clause for loss making units is there.

The environment for the next wage revision as on today is not congenial and is detrimental to the interests of both executives and non- executives. The road to travel may demand perennial struggles to make the Government to yield for getting either the necessary amendments in the existing guidelines or seeking one time exemption to BSNL. Organise the strike effectively so that the closed door open. Let us be united at every level and bring resounding victory to the cause of the strike.

संपादकीय

बड़े पैमाने पर हड़ताल के लिए प्रस्तावना

बीएसएनएल के सभी यूनियनों और एसोसिएशन ने 12 दिसंबर और 13 तारीख को दो दिनों के लिए स्थिति का निश्चयपूर्वक आकलन करने के बाद हड़ताल निर्णय लिया है। हड़ताल के संदेश और महत्व को प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारियों को समझाना चाहिए ताकि इसे एक बहुत सफल बना दिया जाए। सभी संघों द्वारा सूचित होने वाली तैयारी बैठकें केंद्रों में महासचिवों और सीएचक्यू पदाधिकारियों की भागीदारी के साथ आयोजित की जानी चाहिए। जिला संघों को सर्कल सेक्रेटरीज और सर्कल पदाधिकारियों के साथ बैठकों का आयोजन करना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी को हड़ताल में भाग लेने के लिए शाखा स्तर समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अन्य कार्यों जैसे मानवी श्रृंखला और सांसदों को ज्ञापन देने का कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए।

बीएसएनएल के सकारात्मक रवैये के बारे में जानकारी हो सकती है, कंपनी अपने पुनरुद्धार के राह पर होते हुए कर्मचारियों का वेतन पुर्नगठन करने के लिए कंपनी को अनुमति देने के लिए डीओटी को अपना सुझाव /अनुमोदन/अपील हो सकता है। दो दिनों के लिए हड़ताल पर सवाल हो सकता है। हमारे सदस्यों को इसके कारणों को समझाना चाहिए ताकि वे अपने गुस्से को दिखाने के लिए मजबूर स्थिति को समझ सकें।

हड़ताल मजदूरी के संशोधन के सवाल के लिए ही नहीं है, भारत सरकार अलग टावर कंपनी बनाकर हमारे टावर की संपत्तियों को तोड़ने और रणनीतिक साझेदारों के नाम पर निजी दूरसंचार कंपनियों की मदद करने के लिए भारत सरकार के कदमों को रोकना है। कैबिनेट का यह निर्णय अनुचित और अलोकतांत्रिक है क्योंकि कर्मचारियों जो बीएसएनएल हितधारक है बिना परामर्श या जानकारी के बिना और उसे अंधेरे में रखा जा रहा है।

दूसरा मुख्य मुद्दा वेतन संशोधन है हालांकि, भारत सरकार ने 3 पीआरसी की स्थापना की है और सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और डीपीई ने दिशानिर्देश जारी किए हैं, इसमें यह कहा गया है कि बीएसएनएल अपने अधिकारियों 3 पीआरसी लागू नहीं कर सकती। शर्तों बहुत कड़ी हैं और कोई घाटे वाली कंपनी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी वेतन संशोधन को प्राप्त नहीं कर सकती हैं। वेतन संशोधन के संबंध में बीएसएनएल प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदमों को अपने कर्मचारियों के अधिकारियों के प्रति सहानुभूति माना जा सकता है लेकिन मौजूदा डीपीई दिशानिर्देशों के आधार पर उन्हें अधिकृत कार्यवाही के रूप में नहीं लिया जा सकता है। यह बताया गया है कि MOC का यह भी मानना है कि कैबिनेट के फैसले से परे जाने के लिए उनके लिए मुश्किल है।

जब एनएफटीई बीएसएनएल, कर्मचारियों और अधिकारी दोनों पक्षों के साथ द्विपक्षीय वेतन बातचीत समिति की मांग कर रहा है, बीएसएनएल प्रबंधन हमें जवाब दे रहा है कि डीपीई से कोई दिशानिर्देश नहीं है, ताकि उन्हें कर्मचारियों के साथ कोई बातचीत शुरू कर सकें। गैर कार्यकारी अधिकारियों को उनके मजदूरी संशोधन केवल जब वे प्रबंधन के साथ कुछ समझौता हो सकता है। डीपीई ने एनएफटीई को वापस जवाब दिया है, कामगारों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए दिशानिर्देश देने के लिये सक्रिय विचार में हैं। लेकिन यहां तक कि अगर वह दिशानिर्देश जारी किया गया हो, तो यह तब उपयोगी होगा जब घाटे में रहने वाली कंपनी के लिए छूट का खंड होगा।

आज के रूप में वेतन संशोधन के लिए वातावरण अनुकूल नहीं है और दोनों अधिकारियों और गैर-अधिकारियों के हितों के लिए हानिकारक है। मौजूदा दिशा-निर्देशों में आवश्यक संशोधन करने या बीएसएनएल को एक बार छूट देने के लिए सरकार को निर्णय लेने के लिए बार-बार संघर्ष करना होगा। हड़ताल को प्रभावी रूप से करें ताकि बंद दरवाजा खुला हो। हमें हर स्तर पर एकजुट होना चाहिए और हड़ताल के जरिये जीत हासिल करना चाहिए।